गये आक्रमण के फलस्वरूप देश में उत्पन्न राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के वातावरण को स्थायी रूप से कायम रखने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस वातावरण को कायम रखने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और हिंसात्मक उपद्रवों को फूट पड़ने से रोकने के लिये आवश्यक उपायों की लगातार जांच की जाती है और इस बारे में उपयुक्त हिदायतें मौजूद हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.Q. No. 687, DATED 25-8-65

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): In the answer given to part (b) of Unstarred Question No. 687 on the 25th August 1965, regarding Ex-Ministers appointed as Chairmen of Public undertakings, for 'one', two' may be substituted.

---

12 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT (Queries)

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उसे मैं ने नामजूर कर दिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : पंजाबी सूबे पर जो कमेटी बनी है, गृह मंत्री महोदय का उसके....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कहा कि मैंने उसे नामजूर कर दिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप के नामंजूर करने की क्या कोई सीमा होती है ।

अध्यक्ष महोदय : और तो मैं इस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब आप बैठ जाइये ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये यह मुश्किल है कि मेरे पास सात काम रोको प्रस्तावों की नोटिस है । यह हो सकता है कि मैं सातों को एक-एक कर के पढ़ता चला जाऊं और रीजन दे कर कहता जाऊं कि उन को नामंजूर कर दिया । अगर माननीय सदस्य यह चाहें तो मैं तैयार हूं ।

श्री मधु लिमये : संक्षेप में उन के बारे में बतला दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कैसे चल सकेगा । मैंने कई दफे कहा है कि अगर यहां पर इतनी नोटिसेज दी जायेंगी तो कैसे हो सकेगा ।

श्री मधु लिमये : आप संक्षेप में बतला दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य नाम चाहते हैं तो मैं नाम देने के लिए तयार हूं :

श्री मधु लिमये : नाम का सवाल नहीं है, विषयों का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : आज पहले दिन तो मैं यह पढ़ देता हूं लेकिन ऐसा हर रोज नहीं हो सकता । एक एक मेम्बर ने छः छः नोटिसेज दिये हैं कालिंग अटेन्शन के । मैंने इस हाउस से सहमति ली हुई है कि मेम्बर साहब दो नोटिसेज से ज्यादा न दें तब भी छः छः नोटिसेज दी गई हैं । मेम्बर को अपनी नोटिसेज में से चुन लेना चाहिये । चूंकि मैं एक से ज्यादा ऐडमिट नहीं कर सकता इस लिये एक की ही नोटिस देनी चाहिये । मैंने वह भी कहा था कि अगर कुछ शक हो तो वह दूसरी नोटिस दे दे ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने चार वर्षों में पहली नोटिस दी है । चार वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं हमें आये हुए, लेकिन आप ने उस को भी अस्वीकार कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा अब आप बैठ जाइये । मेरे पास एक नोटिस है श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती श्री वारियर, श्री सरजू पाण्डेय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ... सब नाम मैं कैसे पढ़ सकूंगा —

Shri H. N. Mukerjee, Shrimati Renu Chakravartty, Shri Warior, Shri Sarjoo Pandey, Shri Indrajit Gupta— the acceptance by the Prime Minister of an invitation to visit the United States in the present context of continuing US arms pact with Pakistan and the US equivocation over Kashmir's accession to India.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): You will forgive me. We are not interested in listening to names whoever is the signatory or not. But we are interested in the content of it. That is why you will permit me to say just a few words, in regard to your decision which was communicated to me two minutes ago, that you had not been pleased to permit it.

Mr. Speaker: I would just put it to Shri Mukerjee: if I allow him to speak, can I refuse anyone else?

Shri H. N. Mukerjee: Could I make a submission? We are functioning as a group in this House and so many of us have combined on the very first day, and I do claim that we try to behave in as responsible a fashion as parliamentary conventions or regulations require. We have, so many of us, signed this request because we felt it was important. We have found the Prime Minister like a very coy maiden saying yes and no at the same time, at different press conferences and talking all kinds of things which cause complication and utter confusion in the public mind. It seems that only Parliament is the exclusive forum from which information would be withheld. We have found reports circulated by All India Radio and by other sources that the Prime Minister has accepted this invitation to go to America. Then the papers have reported that in Calcutta he told the Press that it was only because of President Johnson convalescing at the present moment and he having a lot of work in Parliament and in the country to do, that he would be going sometime after. But then again he says this morning, according to a press report, that his visit to America is something which other people are talking about but he does not seem to know. It is a very coy way of behaving. The country has enabled the Prime Minister to add a great deal to his stature; he is not like a shy maiden saying yes and no at the same time, when there are political implications in this. Only the other day, he was constrained to refuse to go to America. At the present moment, there is the U.S.-Pak. military pact and from the United States despatch of goods already promised to us had been withheld. And, all kinds of very insulting pinpricks are being practised on this country. In view of this damage to our honour and to our interests, is the Prime Minister going to do this and evade Parlia-

[Shri H. N. Mukerjee]

ment by making statements before press conferences in a very equicocal fashion? That is why, since political questions were involved, we gave notice of this and we wish you to consider this.

श्री रामेश्वरानन्द : मैं कहना चाहता हूं कि इस विकट समय में जब कि हम पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ लड़ रहे हैं, ऐसे समय में पंजाबी सूबे के नाम से कमेटी बना कर गृह मंत्री जी ने जब देश के लोगों के सभी वर्गों में मैत्री की आवश्यकता थी, देशभक्ति की आवश्यकता थी, उस को तोड़ कर लोगों में दरार पैदा कर दी है, भेद भाव खड़ा कर दिया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बात पर विचार अवश्य होना चाहिये। नहीं तो हम चीन और पाकिस्तान से तो क्या लड़ेंगे कहीं ऐसा न हो जाये कि घर में ही झगड़ा खड़ा हो जाये।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव अकाल की स्थिति के बारे में है। मुझे अफसोस होगा अगर इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान इतने राज्यों में गम्भीर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है और हजारों लोग गांव छोड़ कर चले जा रहे हैं। वहां पर अनाज मिल नहीं रहा है। 3 रु० किलो चावल मिलता है, पीने के लिए पानी नहीं प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री जी सब जगह जा कर चिल्लाते हैं "जय किसान और ज्यादा पैदा करो"। अगर इस स्थिति को सरकार रोकने में सफल नहीं होती तो इस को उसकी असफलता ही माना जाना चाहिये। इस लिये मेरा आप से विशेष अनुरोध है कि इस विषय पर आप बहस जरूर होने दीजिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मैंने अपने काम रोको प्रस्ताव में सरकार की इस असफलता की ओर ध्यान दिलाया है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा युद्ध विराम रेखा का जो बराबर उल्लंघन किया जा रहा है उस को रोकने में तथा विदेशी जहाजों में जो हिन्दुस्तानी माल लादा जाता है उस की जब्ती को रोकने में सरकार असमर्थ रही है। साथ ही जो बढ़ते हुए दाम हैं और फैलता हुआ भ्रष्टाचार है उस को रोकने में भी सरकार की जो असफलता है उस की ओर ध्यान दिलाया था। यहां बतलाया गया था कि हिन्दुस्तान एक युद्ध विराम से दूसरे युद्ध विराम की ओर नहीं जायेगा। लेकिन हम तीसरी बार युद्ध विराम कर चुके हैं और इस की कोई गारेन्टी भी नहीं मिली है कि इस वक्त जो युद्ध विराम हुआ है उसका उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा नहीं किया जायेगा। इसलिये मैं इन असफलताओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना काम रोको प्रस्ताव इस आधार पर दिया है कि समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक के माध्यम से सिन्धू जल समझौते के अन्तर्गत 8 करोड़ रु० की नई किस्त देने का निश्चय कर लिया है।

कुछ माननीय सदस्य : दे दिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विश्व बैंक से यह गारेन्टी मिली है कि पाकिस्तान इस 8 करोड़ रु० को हथियार खरीदने या भारत के विपरीत उपयोग करने में नहीं लगायेगा। मेरा अपना निवेदन इस प्रकार का है कि जब भारत सरकार को विश्वस्त जानकारी है कि इच्छोगिल नहर, जहां पाकिस्तानी दरिन्दों ने हमारे जवानों के खून से हाथ रंगे थे, भारतीय पैसे से बनाई गई और

जब भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन जहाजों पर हमारा माल आ रहा था करोड़ों रुपयों का उन को बीच में रोक कर पाकिस्तान ने हमारा माल उतार लिया तो क्या भारत सरकार पाकिस्तान से जिस की निगाह में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई महत्व नहीं है, जिसने अमरीकी हथियारों को इसलिये लिया था कि उनको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और इस लड़ाई में वे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किये गये, उम्मीद करती है कि आठ करोड़ रुपया हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? भारत के पसीने की गाढ़ी कमाई का आठ करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना हिन्दुस्तान की इज्जत को ठोकर मारना होगा। मेरा विश्वास है कि इस सदन में इस विषय पर अवश्य विचार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपका काल अटेंशन नोटिस है काम रोको प्रस्ताव नहीं है।

My submission to the House is that if we allow this procedure to continue it would not be possible to do the business that we have in hand. An adjournment motion is to be tabled where the matter is a very urgent one, where the minds of the hon. Members are so exercised that they cannot proceed with any Government business or whatever other business there may be unless that matter is first discussed and unless the Government can give a satisfactory explanation they would like to throw out the Government. An adjournment motion is tabled where the urgency is such that if it is not discussed immediately something is going to happen which might just injure the interests of the country so much that it might be beyond repair. Unless those circumstances are there an adjournment motion is not to be tabled. Here mostly these are just asking for information. Of course, they are urgent ones, but there was time enough when notices could have been given in the form of questions and information solicited. Even now it can be done. Even Short Notice Questions can be tabled. I do not find any reason in any one of these adjournment motions where unless they are—any one of them—discussed just now probably injury is going to be caused to the interests of the country.

श्री किशन पटनायक : क्या अकाल की स्थिति ऐसी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया। मैंने सातों को बोलने की आज्ञा दे दी। अब और क्या हो सकता है।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, it will be a very interesting study if you just find out how many Short Notice Questions are actually refused and how many are admitted.

Mr. Speaker: If I find that any Short Notice Question is so urgent that it must be answered and the Minister is not going to answer it, I will see that it is put as the first question on the next possible date. That is what I can do.

श्री मधु लिमये : सत्र के आरम्भ में अल्प सूचना प्रश्नों को नहीं स्वीकारा जाता है।

Mr. Speaker: The Prime Minister would make a statement on several issues, I suppose, in two or three days.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): On Friday, the 5th November.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Does, Sir, what you have observed just now, your ruling, if I may call it, unfortunately, mean that what has happened today, the procedure adopted today, will not be a precedent for the future?

Mr. Speaker: It is very unfortunate, of course; but it is there.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Sir, this is not a new procedure. Formerly, when adjournment motions used to be tabled, the Chair used to ask the Members who tabled them to argue out as to how the matter was within the purview of this House and how it was a matter of urgent public importance. Actually, we have given up that practice. Shri Kamath should know that this is not a new procedure that we have followed today.

Shri Hari Vishnu Kamath: Why should she object to what I said? I have supported her point of view. What I asked was: "Does it unfortunately mean that what has happened today will not be a precedent for the future?"

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री महोदय शुक्रवार को बोलेंगे। तो क्या उनकी मोच अब तक चल रही है ? वह टहलते टहलते लाहौर जाने वाले थे, तो पैर में मोच आ गयी और वह बीच में रुक गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक वह मोच चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की इजाजत नहीं देता। मैंने दो तीन काल अटेंशन मोशन एडमिट किये हैं। उनको पूछने के बाद वक्त पर लिया जाएगा। आज पूछने का मौका नहीं मिला था।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : क्या है आप का सवाल ?

श्री यशपाल सिंह : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि पार्लियामेंट से सम्बन्धित किसी भी कार्रवाई का पहले स्पीकर को पता होना चाहिये और हाउस को पता होना चाहिये। लेकिन इससे उल्टा हुआ है। आल इंडिया रेडियो ने प्रसारित कर दिया और अखबारों में लिख दिया गया कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य शुक्रवार को होगा लेकिन स्पीकर को आज पता चला है कि शुक्रवार को होगा। क्या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स इसी तरह चला करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई अजीब बात नहीं है।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Some very important questions which are exercising the minds of hon. Members and the people in the country have been mentioned in these adjournment motions. Government have also announced their intention to make certain statements, possibly on the drought conditions and other matters. Would it not be much better if the House is informed of the subjects on which statements are going to be made from the Government side so that all this trouble may not be there? Once it is known that a statement is going to be made on a particular subject by the Minister of Food, Minister of Home Affairs or the Prime Minister, we on this side will feel reassured and hon. Members opposite will not feel agitated. So, I would suggest that procedure might be adopted.

Mr. Speaker: If I disallow an adjournment motion it does not mean that the same question cannot be raised in any other form. There are various ways in which a discussion can be raised and perhaps I might allow them if a notice is received provided they are important questions which should be discussed. I have only decided that they cannot be allowed as adjournment motions; that is all; not that they would not be discussed at all. If a proper notice is given I will see that a discussion takes place if the subject is important.

Shri Harish Chandra Mathur: I only wanted to smoothen the procedure.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have tabled a calling attention notice. You have just now said that certain calling attention notices are under consideration.

Mr. Speaker: I only said that I admitted three of them.

Shri S. M. Banerjee: We are told that the hon. Prime Minister and other Cabinet Ministers are going to make some statements. We find from the papers that there is going to be a long-term agreement on PL 480. Since the entire House knows that every bullet which killed the jawans was supplied by America, my only request is.....

Mr. Speaker: What is his point?

Shri S. M. Banerjee: I am not making any comments. The renewal of this agreement is in the offing. Since we are all very much agitated on this question, let the Government take us into confidence and let the whole matter be discussed before the agreement is signed. No decision should be taken without consulting Parliament.

Mr. Speaker: Now papers to be laid on the Table.

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, आप ने एडजर्नमेंट मोशन के बारे में जो क्राइटेरियन बताया क्या अकाल की स्थिति पर वह लागू नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं होता ।

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

SUMMARY OF REPORT OF THE GOVERNOR OF KERALA

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): I beg to lay on the Table a Summary of the Report of the Governor of Kerala dated the 17th October, 1965, to the Union Home Minister. [*Placed in Library. See* No. LT-4990/65].

STATEMENT GIVING REASONS FOR IMMEDIATE LEGISLATION BY RAILWAYS (EMPLOYMENT OF MEMBERS OF ARMED FORCES) ORDINANCE

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): I beg to lay on the Table a copy of the Explanatory Statement giving reasons for immediate legislation by the Railways (Employment of Members of the Armed Forces) Ordinance, 1965, under rule 71(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-4991/65.]

STATEMENT CORRECTING ANSWERS TO S.Q. 599 RE. FINANCE AGENCIES

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): I beg

(1) to lay on the Table a statement correcting the answers given on the 14th September, 1965 to certain supplementaries by Shri Shree Narayan Das on Starred Question No. 599 regarding Finance Agencies. [*Placed in Library. See* No. LT-4992/65.]

(2) to re-lay on the Table a copy of Notification S.R.O. 265/64 published in Kerala Gazette dated the 1st September 1964, containing Kerala Hillman Rules, 1964, under section 77 of the Kerala Forest Act, 1961, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [*Placed in Library. See* No. LT-4839/65.]